

14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEM-
BERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-THIRD REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

Mr. Deputy-Speaker: The question is . . .

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I request that the time allotted for Shri Yadava's Resolution may be extended by one hour.

Mr. Deputy-Speaker: That is not in the report. We are adopting the report now. We shall take that up later.

The question is:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: DISPARITY IN
INCOME—contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of the Resolution on Disparity in Income moved by Shri Bhisma Prasad Yadava on the 22nd April, 1964. Shri Yadava has already taken 22 minutes.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, the time should be extended for it. It is a very important resolution.

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी): इसमें और समय बढ़ाया जाये क्योंकि बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Let him finish his speech. The hon. Member may take two or three minutes and finish his speech.

श्री भी० प्र० यादव (केसरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार कह रहा था कि हमारे देश में आर्थिक विषमता कितनी बढ़ रही है और मैं ने इस और सरकार का ध्यान दिलाया था।

अब मैं सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट की ओर भी दिलाना चाहता हूँ जो कि गांव वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाशित हुई है। उस में साफ तौर पर बताया गया है कि गांवों की स्थिति किस तरह की है। उस में कहा गया है कि गांव वालों पर कुल ऋण ३० अरब है। सारे देश में गांवों में ७ करोड़ ४० लाख परिवार रहते हैं, इस प्रकार अगर औसत निकाला जाये तो प्रति परिवार ४०० रुपये का औसत करज का आता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सारा ऋण ब्रिटिश शासनकाल से लदा हुआ चला आ रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक साल में यानी सन् १९६१-६२ की साल में गांव वालों ने १३ अरब ३२ लाख का कर्जा लिया है। उस रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया है कि इस कर्ज में से, यानी ३० अरब के कर्ज में से ८ प्रति शत सहकारी समितियों से लिया गया है और शेष ६२ प्रति शत महाजनों से ऊंची दर पर लिया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि हमारी सहकारी समितियाँ कितनी सफल हो रही हैं।

हम ने योजना बनाते समय यह ध्यान रखा है कि गांव का हर आदमी हम को अपना वित्तीय सहयोग देगा। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम जो गांव वालों से आर्थिक सहयोग की आशा किये हुए थे वह पूरी नहीं हुई है क्योंकि उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांवों की गरीबी